अग्रणी बैंक योजना

श्रीमती पूजा शर्मा, एजीएम और संकाय सदस्य, सीएबी, पुणे द्वारा संकलित। उनसे ***pujasharma@rbi.org.in*** पर संपर्क किया जा सकता है

अस्वीकरण: सामग्री केवल शैक्षणिक और सूचना उद्देश्यों के लिए है। कृपया इस संबंध में संबंधित कानूनों, परिपत्रों, निर्देशों आदि से मार्गदर्शन लें। इस सामग्री में व्यक्त विचार लेखक के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक या कृषि बैंकिंग कॉलेज, पुणे के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। सामान्य अस्वीकरण लागू होगा।

अग्रणी बैंक योजना

अग्रणी बैंक योजना

1. पृष्ठभूमि

समाज के वंचित/बहिष्कृत वर्गों का वित्तीय समावेश आर्थिक स्थिरता और प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में, वित्तीय समावेशन की दिशा में किए गए शुरुआती प्रयासों में अग्रणी बैंक योजना और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार दिशानिर्देश शामिल हैं। शीर्ष बैंक योजना के तहत प्रत्येक जिले को एक बैंक सौंपा गया है (शुरुआत में यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था), जिसे जिले के शीर्ष बैंक के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न मंचों के माध्यम से बैंकों और अन्य विकास एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना है ताकि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों में बैंक वित्त के प्रवाह को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास में बैंकों की भूमिका को बढ़ावा दिया जा सके। . 'शीर्ष बैंक' जिले में गतिविधियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। क्रेडिट संस्थानों और सरकार के प्रयासों के समन्वय के लिए नेतृत्व की भूमिका निभाने की उम्मीद है। प्रत्येक राज्य को एक राष्ट्रीयकृत बैंक भी सौंपा जाता है, जिसे संयोजक बैंक के रूप में जाना जाता है, जो उस राज्य के सभी अग्रणी बैंकों के प्रयासों का समन्वय करता है। यह कहना दूर की कौड़ी लाना नहीं है कि एलबीएस के बैंक राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मुख्य वाहन होने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में, अग्रणी बैंक की भूमिका त्रि-आयामी होती है।

वाणिज्यिक ऋण संस्थाएं	संसाधन जुटाना और अग्रिम देना
योजना एजेंसी	• आवश्यकताओं और समस्याओं को समझना और लक्ष्य बनाकर उनका समाधान करना
विकास अजेंसी	• उत्प्रेरक एजेंट के रूप में कार्य करना और जिलों के पिछड़े और अविकसित क्षेत्रों का विकास करना

चित्र 1

साथ ही, स्पष्ट रूप से ऐसा कोई इरादा नहीं है कि किसी जिले में अग्रणी बैंक का बैंकिंग व्यवसाय का एकाधिकार हो। जिस बैंक को प्रमुख भूमिका सौंपी जाती है, उससे संघ के नेता के रूप में कार्य करने और शाखा विस्तार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों और क्रेडिट अंतराल से पीड़ित क्षेत्रों की पहचान करने की अपेक्षा की जाती है। इसे जिले में कार्यरत अन्य बैंकों के सहयोग, शाखाएं खोलने के साथ-साथ ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए।

1.1 योजना की उत्पत्ति: अग्रणी बैंक योजना (एलबीएस) की उत्पत्ति का पता सामाजिक उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक ढांचे पर प्रो. डी. आर. गाडगिल की अध्यक्षता वाले अध्ययन समूह से लगाया जा सकता है, जिसने अक्टूबर 1969 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अध्ययन समूह ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया कि वाणिज्यिक बैंकों की ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त उपस्थिति नहीं थी और आवश्यक ग्रामीण अभिविन्यास का भी अभाव था। समूह द्वारा यह पाया गया कि जून 1967 तक वाणिज्यिक बैंकों ने केवल 5000 गांवों में प्रवेश किया था और कृषि के लिए संस्थागत ऋण में उनका हिस्सा कुल 39% में से केवल 1% था, शेष सहकारी समितियों द्वारा पूरा किया जा रहा था।

1.2 इससे पता चलता है कि सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष रूप से पिछड़े क्षेत्रों की बैंकिंग जरूरतों पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, जिसमें कृषि, एसएसआई और संबद्ध गतिविधियों (उस समय आरबीआई द्वारा परिभाषित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों) की ऋण आवश्यकताएं शामिल थीं। इसलिए, अध्ययन समूह ने ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बैंकिंग और ऋण संरचना के विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए एक 'क्षेत्रीय दृष्टिकोण' अपनाने की सिफारिश की।

1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शाखा विस्तार कार्यक्रम पर बैंकरों की एक अन्य समिति आरबीआई द्वारा श्री एफ.के.एफ. नरीमन की अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट (नवंबर 1969) में क्षेत्र दृष्टिकोण के विचार का समर्थन किया था, जिसमें सिफारिश की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अपने ऋण का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के लिए सामाजिक जिम्मेदारियों के लिए प्रत्येक बैंक को कुछ जिलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां उसे 'अग्रणी बैंक' के रूप में कार्य करना चाहिए। उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर 1969 में अग्रणी बैंक योजना शुरू की गई थी। 31 मार्च 2022 तक, देश के 734 जिलों में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एक निजी क्षेत्र के बैंक को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.4 एलबीएस की शुरुआत के चार दशकों में, देश में कई बदलाव हुए हैं, खासकर 1991 के बाद वैश्वीकरण की शुरुआत और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ। सुधारों में वित्तीय क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय कुछ प्रमुख सुधार हैं -

क) 1989 में **सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण** (SAA) की शुरुआत एक प्रमुख कार्य था। इसे पीडी ओझा की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों के आधार पर अपनाया गया था। उन्होंने देखा कि एलबीएस पूरे जिलों में प्रभावी नहीं था क्योंकि गांवों में विकास एक समान नहीं था। एसएए के तहत, गांवों की पहचान की गई और बैंक शाखाओं को उनकी निकटता और निकटता के आधार पर और क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाकर सौंपा गया। प्रत्येक शाखा के सेवा क्षेत्र के लिए वार्षिक आधार पर ऋण योजनाएँ तैयार की जाती थीं जिसमें विभिन्न विकास एजेंसियों और ऋण संस्थानों के बीच समन्वय शामिल था। नामित बैंक शाखाओं को गांवों के आवंटन के कारण, 'सेवा क्षेत्र शाखाओं' की गतिविधियां आवंटित गांवों तक ही सीमित थीं और वे कई बार ऐसा करने की स्थिति में होने के बावजूद अपने सेवा क्षेत्रों के बाहर वित्तीय सहायता प्रदान करने में असमर्थ थे। इसी तरह, इन गांवों से संबंधित उधारकर्ताओं को अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए 'नामित बैंक शाखाओं' से संपर्क करने की आवश्यकता थी और वे किसी अन्य बैंक शाखाओं की सेवाओं का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं थे, भले ही वे नामित द्वारा प्रदान की गई सेवाओं से संतुष्ट हों या नहीं।

ख) बाद में, कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण प्रवाह पर सलाहकार समिति (अध्यक्ष प्रो. वी.एस.व्यास, जून 2004) ने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के नियोजित और व्यवस्थित विकास के लिए शुरू किए गए सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण ने कठोरता विकसित की थी और एक के रूप में कार्य किया था। लचीलापन प्रदान करने के लिए अंतर्निहित उपायों के बावजूद अड़चन थी। कमिटी ने सुझाव दिया कि लचीलेपन की इस विशेषता को बनाए रखने की जरूरत है और सेवा क्षेत्र की अवधारणा को केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण अब केवल सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए दिसंबर 2004 से लागू है।

ग) वाणिज्यिक बैंक अपनी वित्तीय स्थिति पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार किया था। उनके पूंजी पर्याप्तता अनुपात और प्रावधान मानक सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप थे। हालांकि निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों दोनों के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के दायित्व जारी रहे हैं, इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है कि देश के बड़े वर्ग की जनसंख्या औपचारिक बैंकिंग संरचना से बाहर रहती है और कुछ क्षेत्रों में वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र पिछड़ते रहते हैं। जबकि समाज के अधिक संवेदनशील क्षेत्रों/वर्गों को ऋण के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतियां मौजूद थीं, समय पर जानकारी प्राप्त करने और परिणामों का बेहतर मूल्यांकन करने के अलावा, जमीनी स्तर पर इन नीतियों का अधिक से अधिक प्रसार और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी। इसलिए, योजना की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग क्षेत्र में हाल के विकास पर ध्यान देने के साथ एलबीएस की समीक्षा के लिए अध्यक्ष के रूप में श्रीमती उषा थोरात के साथ 2008 में आरबीआई द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति ने विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा की। राज्य सरकारों, बैंकों, विकास संस्थानों, शिक्षाविदों, गैर सरकारी संगठनों, एमएफआई, आदि ने नोट किया कि यह योजना शाखा विस्तार, जमा जुटाने और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण / अर्ध शहरी क्षेत्रों में सुधार के अपने मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोगी रही है। इस बात पर भारी सहमति थी कि योजना को जारी रखने की जरूरत है। अग्रणी बैंक तंत्र को यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पाया गया कि बैंक और राज्य सरकारें सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए समावेशी विकास हासिल करने के लिए मिलकर काम करें।

घ) 2009 के बाद से वित्तीय क्षेत्र में हुए सभी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, जब पिछली समीक्षा उषा थोराट की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा की गई थी, जिसे योजना की प्रभावशीलता और सुधार के उपाय सुझाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एक "कार्यकारी निदेशकों की समिति" का अध्ययन करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित किया गया था। । ईडी की समिति ने 2018 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और विभिन्न हितधारकों के साथ सिफारिशों पर चर्चा की गई। प्राप्त फीडबैक के आधार पर 6 अप्रैल 2018 को एलबीएस के तहत संशोधित निर्देश जारी किए गए, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं।

• नीति और परिचालन संबंधी मुद्दों को विभाजित करके राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के कामकाज को सुव्यवस्थित करना जिससे परिचालन संबंधी मुद्दों को विशिष्ट उप-समितियों द्वारा संबोधित किया जाएगा और एक संचालन उपसमिति एसएलबीसी के लिए प्राथमिक एजेंडा मदों पर निर्णय करेगी;

• ऐसे मामलों में जहां एसएलबीसी संयोजक बैंक के प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यकारी निदेशक एसएलबीसी बैठकों में भाग लेने में असमर्थ हैं, आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव/विकास आयुक्त के साथ बैठकों की सह-अध्यक्षता करेंगे।

• बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अग्रणी बैंक योजना के तहत बैंकों के कॉर्पोरेट व्यवसाय लक्ष्यों को वार्षिक ऋण योजनाओं (एसीपी) के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक राज्य में नियंत्रण कार्यालयों को अपनी आंतरिक व्यावसायिक

योजनाओं को एसीपी के साथ सिंक्रनाइज़ करना चाहिए।

• सभी सहभागी बैंकों के संबंधित सीबीएस के माध्यम से डेटा के सीधे संग्रह सहित एसएलबीसी की वेबसाइटों के प्रबंधन के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण।

• यह सुनिश्चित करके कि सभी शाखा प्रबंधक BLBC बैठकों में भाग लें और अपने मूल्यवान इनपुट के साथ विचार-विमर्श को समृद्ध करते हुए, अग्रणी बैंक योजना के आधार स्तर पर संचालित होने वाले BLBC फोरम को सुदृढ़ बनाना। बैंकों के नियंत्रक प्रमुख भी चुनिंदा बीएलबीसी बैठकों में शामिल हो सकते हैं।

• ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) को विशेष रूप से डीसीसी स्तर पर एलबीएस के विभिन्न मंचों पर अधिक सक्रिय रूप से शामिल और निगरानी की जानी चाहिए।

• क्षेत्र में ऋण अवशोषण क्षमता को बढ़ाने के लिए कौशल के विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के नवीनीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए । आरएसईटीआई को जिले में ग्रामीण युवाओं के आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के लिए कौशल मानचित्रण और क्षेत्र की क्षमता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले / ब्लॉक के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करना चाहिए।

• बिना बैंक वाले ग्रामीण केंद्रों (यूआरसी) में सीबीएस-सक्षम बैंकिंग आउटलेट स्थापित करने पर अधिक केंद्रित समीक्षाओं के लिए आरबीआई द्वारा एसएलबीसी बैठकों के लिए एक संशोधित एजेंडा दिया गया था; बीसी के संचालन; कनेक्टिविटी सहित भुगतान के डिजिटल तरीके; प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी); वित्तीय साक्षरता पहल; भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण; और ग्रामीण बुनियादी ढांचे/ऋण अवशोषण क्षमता में सुधार पर चर्चा।

2. योजना का प्रशासन:

क) जिलों का आवंटन - प्रत्येक जिले में नामित बैंकों को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारी सौंपना - इस उद्देश्य के लिए तैयार की गई विस्तृत प्रक्रिया का पालन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। जिस बैंक को प्रमुख जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे लीड बैंक कहा जाता है और ऐसे जिलों को अग्रणी जिले कहा जाएगा।

b) संगठनात्मक सेटअप - लीड बैंक योजना में लीड बैंक, अन्य वाणिज्यिक बैंक (नॉन लीड बैंक), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRB), सहकारी बैंक, राज्य वित्तीय निगम, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIB), RBI, NABARD और सरकार की अन्य विकास एजेंसियांजैसे अन्य वित्तीय संस्थानों की भागीदारी शामिल है। । लीड बैंक योजना का संगठनात्मक ढांचा नीचे दिखाया गया है।

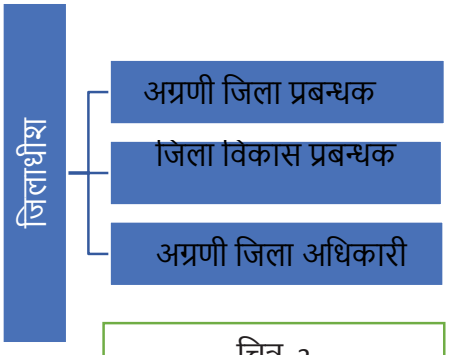

चित्र 2

- जिला कलेक्टर जिले की पूरी मशीनरी पर नियंत्रण रखता है और योजना के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- एलडीएम अग्रणी बैंक का प्रतिनिधि है और विभिन्न सरकारी एजेंसियों के संबंधित विभागों सहित अग्रणी बैंक के क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालय और सहभागी संस्थानों की सहायक भूमिका के साथ योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। एलडीएम की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित किया जाता है कि एलडीएम का कार्यालय उचित ढांचागत समर्थन के साथ पर्याप्त रूप से मजबूत हो।
- योजना के तहत नाबार्ड के प्रतिनिधि-अधिकारी को डीडीएम के रूप में नामित किया गया है. उसे अन्य बातों के साथ-साथ संभावित लिंक योजना (पीएलपी) तैयार करने और योजना के तहत आयोजित विभिन्न बैठकों में भाग लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- बैठकों में आरबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले आरबीआई के अधिकारी को एलडीओ कहा जाता है। उन्हें जिले के विकास एजेंट के रूप में विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।
- लीड बैंक योजना ने एलडीएम, डीडीएम और एलडीओ के कार्यों और कर्तव्यों और योजना के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। योजना को विस्तार से पढ़ने के लिए आप भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध 01 अप्रैल 2022 का मास्टर परिपत्र FIDD.CO.LBS.BC.No.02/02.01.001/2022-23 देख सकते हैं।

2. समन्वय के मंच: ग्रामीण उधार विकास के अच्छी तरह से डिजाइन किए गए कार्यक्रमों से ठीक से जुड़ा हुआ है। यह न केवल संबंधित और जिले में अन्य विकास एजेंसियों और विभिन्न क्रेडिट संस्थानों के बीच बल्कि क्रेडिट संस्थानों और सरकार के बीच भी प्रभावी सहयोग और समन्वय की मांग करता है। इसलिए उपयुक्त मंचों का निर्माण किया जाना चाहिए जहां ये दोनों एजेंसियां विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समय-समय पर मिल सकें। सरकार और बैंकों दोनों द्वारा विकसित योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिला और राज्य स्तर पर जो मंच वर्तमान में स्थापित किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं –

(i) राज्य स्तर पर - राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी)

(ii) यह राज्य के विकास के लिए पर्याप्त समन्वय बनाने के लिए एक शीर्ष अंतर-संस्थागत मंच है। एसएलबीसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाती हैं। चूंकि एसएलबीसी मुख्य रूप से राज्य स्तर पर बैंकरों की एक समिति है जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इसलिए आरबीआई द्वारा अग्रणी बैंक योजना के तहत राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठकों के संचालन पर निदर्शी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) SLBC की अध्यक्षता संयोजक बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/संयोजक बैंक के कार्यकारी निदेशक करते हैं। इसमें वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी, राज्य सहकारी बैंकों, आरबीआई, नाबार्ड के प्रतिनिधि, सरकारी विभागों के प्रमुख शामिल हैं, जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति / जनजाति आयोग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग आदि के प्रतिनिधि और वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो एक राज्य में एक साथ आते हैं और नीति कार्यान्वयन स्तर पर समन्वय समस्याओं का समाधान करते हैं। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे खुदरा व्यापारियों, निर्यातकों और किसान संघ आदि के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि एसएलबीसी की बैठकों में उनकी विशिष्ट समस्याओं, यदि कोई हो, पर चर्चा करने के लिए विशेष आमंत्रित होते हैं।

(iv) जिला स्तर पर - जिला सलाहकार समितियां (डीसीसी) योजना के तहत विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों को लागू करने में गतिविधियों के समन्वय के लिए बैंकरों के साथ-साथ सरकारी एजेंसियों/विभागों के लिए जिला स्तर पर एक आम मंच है। डीसीसी की बैठकों के अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं। आरबीआई, नाबार्ड, जिले के सभी वाणिज्यिक बैंक, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), आरआरबी, विभिन्न राज्य सरकार के विभागों और संबद्ध एजेंसियों सहित सहकारी बैंक डीसीसी के सदस्य हैं। एलडीओ डीसीसी के सदस्य के रूप में रिजर्व बैंक का प्रतिनिधित्व करता है। एलडीएम डीसीसी की बैठक बुलाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान (MSME-DI) के निदेशक उन जिलों में आमंत्रित होते हैं, जहां MSMEs से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए MSME क्लस्टर स्थित हैं।

इस मंच का गठन बैंकिंग आयोग (1972) के कहने पर किया गया था और यह जिला विकास योजनाओं के मामले में परामर्श की आवश्यकता के कारण कमोबेश स्वेच्छा से अस्तित्व में आया था। वर्षों से, यह एलबीएस के एक अभिन्न अंग के रूप में विकसित हुआ है। इस बैठक में नियमित रूप से चर्चा किए जाने वाले विभिन्न मुद्दों को एलबीएस के तहत निर्धारित किया गया है। विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जिलों में डीसीसी की छोटी कार्यात्मक उप-समितियां भी गठित की जाती हैं।

जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) - डीसीपी/एसीपी में शामिल योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के मूल्यांकन, समस्या क्षेत्रों की पहचान करने और उपयुक्त उपचारात्मक कदम तैयार करने के लिए एक त्रैमासिक मंच है। लीड बैंक योजना के कामकाज की समीक्षा के लिए कार्य समूह ने देखा कि इस मंच ने न केवल अग्रणी बैंक योजना में भाग लेने वाले विभिन्न संगठनों और ग्रामीण विकास से जुड़ी गैर-सरकारी एजेंसियों को एक साथ लाने के लिए उपयोगी के रूप में काम किया है, बल्कि एक तरह से विकसित भी किया है। डीसीपी/एएपी के तहत प्रदर्शन की सामान्य समीक्षा के लिए मंचों में ताकि जिले में कार्यान्वयन के तहत विकास कार्यक्रमों में गैर-अधिकारियों सहित सभी संबंधित एजेंसियों की नियमित भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

डीएलआरसी के निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर डीसीसी की बैठकों में चर्चा किए जाने की आवश्यकता है। डीएलआरसी के साथ गैर-अधिकारियों का जुड़ाव विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अच्छी तरह से सूचित सार्वजनिक प्रतिक्रिया, वित्तीय संस्थानों और सरकारी एजेंसियों दोनों द्वारा उनके कार्यान्वयन की गति और गुणवत्ता की प्रतिक्रिया प्राप्त करने में उपयोगी माना जाता है। सभी स्थानीय सांसदों और विधायकों को भी अप्रैल 1989 से अग्रणी बैंकों द्वारा आयोजित डीएलआरसी की बैठकों में आमंत्रित किया जाना है। विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग, एससी/एसटी निगम आदि के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ग्रामीण ऋण के लाभार्थियों के समूहों के प्रतिनिधियों को भी डीएलआरसी के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है। चूंकि इन बैठकों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इन्हें तिमाही आधार पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है और अग्रणी बैंकों को इन बैठकों में भाग लेने के लिए सांसदों/विधायकों और जिला परिषद प्रमुखों को निरपवाद रूप से आमंत्रित करने की सलाह दी गई है। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे सांसदों और अन्य जन प्रतिनिधियों को उनके द्वारा जिलों में आयोजित कार्यों की अध्यक्षता करने के लिए निरपवाद रूप से आमंत्रित करें, जैसे कि नई शाखाएं खोलना, किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण आदि।

iii) ब्लॉक स्तर पर - ब्लॉक स्तरीय बैंकर समिति (बीएलबीसी) एक तरफ क्रेडिट संस्थानों और दूसरी तरफ क्षेत्र स्तर की विकास एजेंसियों के बीच समन्वय प्राप्त करने के लिए एक मंच है। फोरम ब्लॉक क्रेडिट योजना के कार्यान्वयन को तैयार करता है और समीक्षा करता है और बैंकों के क्रेडिट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में परिचालन संबंधी समस्याओं का समाधान भी करता है। जिले के एलडीएम बीएलबीसी के अध्यक्ष हैं। डीसीसीबी एवं आरआरबी सहित प्रखंड में कार्यरत सभी बैंक, प्रखंड विकास अधिकारी, प्रखंड में तकनीकी अधिकारी जैसे कृषि, उद्योग एवं सहकारिता के विस्तार अधिकारी आदि समिति के सदस्य हैं. BLBC की बैठकें त्रैमासिक अंतराल पर आयोजित की जाती हैं। आरबीआई के एलडीओ चुनिंदा बैठक में भाग लेते हैं और नाबार्ड के डीडीएम को बीएलबीसी की सभी बैठकों में भाग लेना चाहिए। पंचायत समितियों के प्रतिनिधियों को भी अर्धवार्षिक अंतराल पर बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि ऋण योजना अभ्यास में ग्रामीण विकास पर अपने ज्ञान और अनुभव को साझा किया जा सके।

2. अग्रणी बैंक योजना का कार्यान्वयन

4.1 ऋण योजनाएँ तैयार करना - अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन में नियोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विकास के लिए मौजूदा संभावनाओं का मानचित्रण करने के लिए एक बॉटम-अप दृष्टिकोण अपनाया जाता है। एलबीएस के तहत, विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुमानित ब्लॉक-वार/गतिविधि-वार क्षमता की पहचान के साथ योजना शुरू होती है। बैंक क्रेडिट के माध्यम से विकाससंभावित लिंक्ड क्रेडिट प्लान (पीएलपी) विकेंद्रीकृत क्रेडिट योजना की दिशा में एक कदम है, जिसका मूल उद्देश्य मौजूदा क्षमता का मानचित्रण करना है।
पीएलपी जिले के निम्नलिखित मानकों को ध्यान में रखते हैं-
• दीर्घकालिक भौतिक क्षमता,
• अवसंरचना सहायता की उपलब्धता
• विपणन सुविधाएं
• सरकार की नीतियां/कार्यक्रम आदि।

नाबार्ड के डीडीएम यह सुनिश्चित करते हैं कि पीएलपी अधिक केंद्रित और कार्यान्वयन योग्य हों ताकि बैंक शाखा क्रेडिट योजना तैयार करते समय उनका अधिक लाभकारी उपयोग कर सकें। पीएलपी को स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर देना चाहिए। पीएलपी तैयार करते समय, प्रक्रियाओं और परियोजनाओं की पहचान करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जो:

ए. कार्बन फुट-प्रिंट कम करें
बी. उर्वरकों के अति प्रयोग को रोकें
सी. पानी का कुशल उपयोग सुनिश्चित करें
डी. कृषि प्रदूषण के मुद्दों ध्यान दें।

योजनाओं को जैविक खेती, जैव गतिशील खेती, पर्माकल्चर और टिकाऊ लघु-स्तरीय खेती जैसी नवीन कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और किसानों के बाजारों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस तरह की पहल को उचित निवेश और परियोजना वित्त ढांचे द्वारा समर्थित होना चाहिए।

ब्लॉक वार/क्रेडिट वार पीएलपी के आधार पर, जिसे डीडीएम द्वारा जिले में बैंकों के नियंत्रण कार्यालयों के साथ साझा किया जाता है, बैंकों को शाखा स्तर पर वार्षिक क्रेडिट प्लान तैयार करने की सलाह दी जाती है, जो जिला स्तरीय योजना तैयार करने के लिए संकलित की जाती हैं और इसके बाद जिला योजनाओं को राज्य स्तरीय योजना तैयार करने के लिए संकलित किया जाता है। यह क्रेडिट प्लानिंग एक्सरसाइज को बॉटम-अप अप्रोच बनाता है।

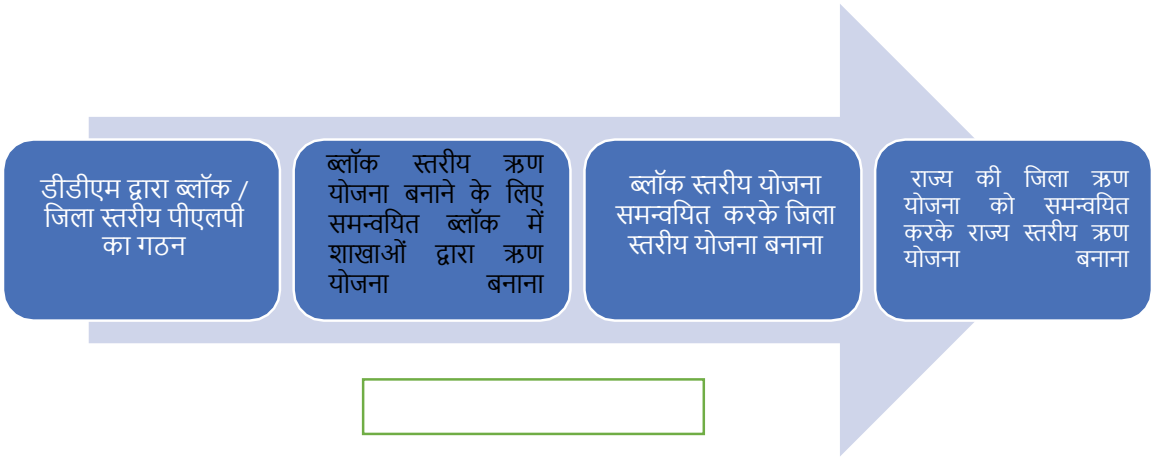

चित्र 3

4.1 योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए डेटा प्रवाह - विभिन्न एलबीएस मंचों की त्रैमासिक बैठकों में एसएलबीसी, डीसीसी और बीएलबीसी, सभी चर्चाएं मुख्य रूप से वार्षिक ऋण योजना के तहत आवंटित लक्ष्य की तुलना में ऋणों के वितरण में बैंकों के प्रदर्शन पर केंद्रित होती हैं। इस उद्देश्य के लिए बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की अखंडता और समयबद्धता योजना की स्थापना के बाद से एक चुनौती रही है क्योंकि इस डेटा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैन्युअल रूप से संकलित किया जाता है और एसएलबीसी संयोजक बैंकों के डेटा प्रबंधन सिस्टम में दर्ज किया जाता है। यह डेटा किस हद तक संबंधित बैंकों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) में मौजूद डेटा से मेल खाता है, यह भी काफी भिन्न होता है। इसलिए, यह सिफारिश की गई थी

ईडी समिति द्वारा प्रत्येक एसएलबीसी द्वारा अनुरक्षित वेबसाइट पर एक मानकीकृत प्रणाली विकसित की जाए ताकि ब्लॉक, जिला और राज्य से संबंधित डेटा को अपलोड और डाउनलोड किया जा सके। प्रक्रिया में न्यूनतम स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप रखने की दृष्टि से प्रासंगिक डेटा बैंकों के सीबीएस और/या एमआईएस से सीधे डाउनलोड करने योग्य होना चाहिए। इस क्षेत्र में परिकल्पित हस्तक्षेप से संबंधित प्रक्रिया अग्रणी बैंक योजना में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है, जिसे निम्नलिखित उदाहरण में दर्शाया गया है।

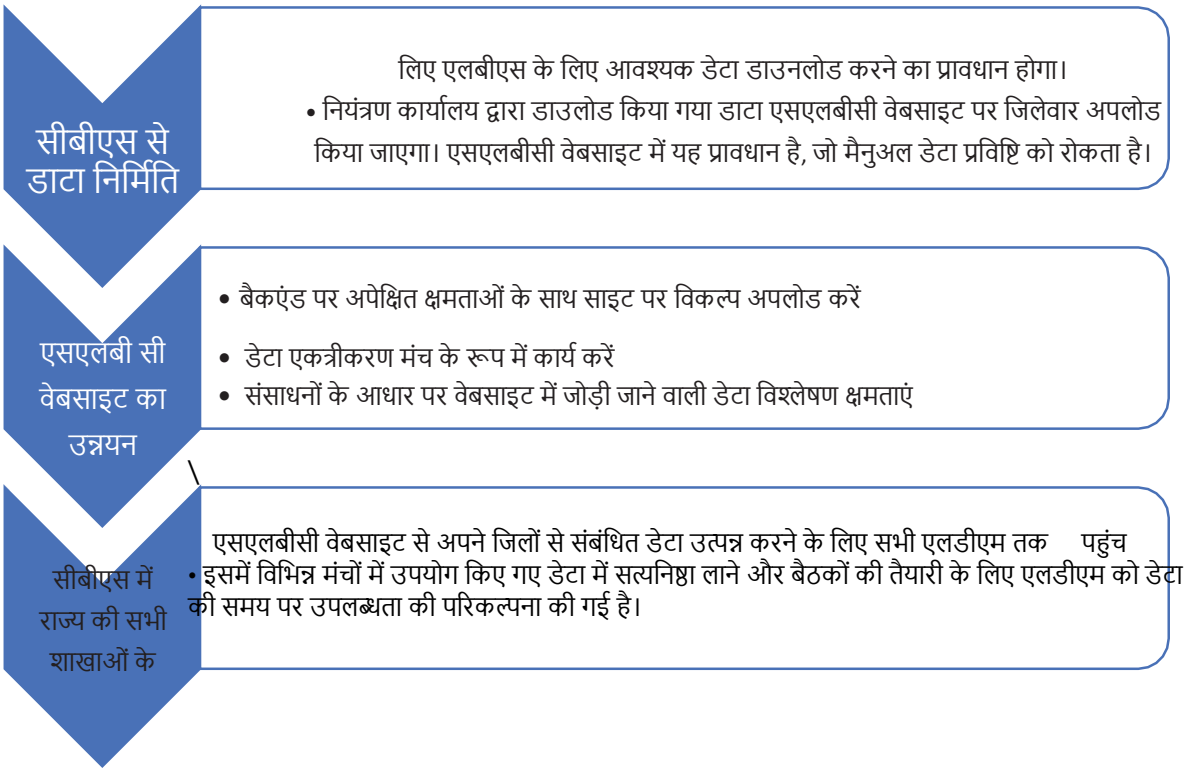

चित्र 4

*****